

country; people manually clean dry toilets everyday while braving dangerous infections, sometimes for a paltry sum of Rs. 10/- per household.

In a recent incident, in New Delhi, three men died while cleaning a sewer inside the Indira Gandhi National Centre for the Arts. They have collapsed after inhaling toxic gases from the sewer.

The Safai Karmachari Andolan had organized a protest where manual scavengers, mostly women, demanded a complete ban on the practice.

Our Party called for strict implementation of the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 and sought a time-bound programme to end manual scavenging. We demand serious efforts on the part of the Government to prevent death of labourers due to asphyxiation while cleaning sewerage network.

The Government should consider passing the new Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012 with amendments on priority. In the new Bill, the definition of 'manual scavenger' is according to our demand. Thank You.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with this issue.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with it.

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड) : सर, मैं इनके उल्लेख से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I also associate myself with this issue.

SHRI N.K. SINGH (Bihar): Sir, I also associate myself with this issue.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, I associate myself with this issue.

SHRI AVTAR SINGH KARIMPURI (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with it.

Problems arising due to non-functioning of Airport Authority at Kolkata Airport

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, there was a consensus between the Airport Authority and the Aviation Ministry on the one side and the Employees Union and former Left Front Government of West Bengal on the other side. A consensus was arrived that the Netaji Subhas Airport at Kolkata

would be modernised by the Airport Authority itself and the employees would neither be retrenched nor transferred or be declared as surplus. Now renovation work has been more or less completed, but the Airport Authority has embarked upon a scheme to replace the permanent employees by hired contract workers through outsourcing on the plea of the so called inefficiency of the employees.

Recently, a tender has been floated in this regard. Sir, if new employees are needed for the expansion of the airport and for its efficient functioning, then, the Airports Authority itself can recruit such people. Sir, I appeal to the hon. Minister of Civil Aviation to direct the management to withdraw the order and instruct the Authority to immediately repair the defects existing in the new structure and ensure smooth working environment thereby ensuring a decent passenger service.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Bhattacharya to associate...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, only the maintenance work should be outsourced.

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Sir, I associate myself with it.

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal) : Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just associate yourself with it in one or two sentences.

SHRI P. BHATTACHARYA : Sir, I do not know whether you had any opportunity to visit the Kolkata Airport. If you happen to go there, you may find it to be a very beautiful airport. But once you enter the Airport, suddenly, you will see a glass pane breaking and hitting your head. And, if you enter the Airport in a rainy season, you have to carry an umbrella with you. Otherwise, it is very difficult to go inside. I have, repeatedly, complained about it to the Airports Authority. But, unfortunately, I do not know what these people are doing except transferring the workers this way and that way.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you conclude.

SHRI P. BHATTACHARYA: They are doing nothing. Sir, it requires a serious investigation. Malpractices are going on there. The matter cannot be thrown away. It requires a serious investigation as to why these things are happening.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister of Civil Aviation is here. Mr. Minister, you kindly get it examined.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, I would like to add something here. The hon. Prime Minister is here. He chairs the Committee on Infrastructure. That Committee had taken a decision that as far as the Airports of Kolkata and Chennai were concerned, they would be renovated by the Airports Authority and whatever they wanted to outsource, they would decide. But now we hear that they are being privatized...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no...*(Interruptions)*

SHRI SITARAM YECHURY: That is also an issue that needs to be answered by the Minister.

शुश्री ढायावती (उत्तर प्रदेश) : ढाननीय उपसभापति जी, ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the subject?

शुश्री ढायावती : वह अभी ढैं बताने जा रही हूँ। यह बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If it is about clarifications, then, I will give you time...*(Interruptions)*...

शुश्री ढायावती : ढाननीय उपसभापति जी, आज ढैं ढाननीय सदन ढें एक ऐसा ढहतत्वपूर्ण ढुद्दा उढाना चाहती हूँ, जो देश के करोड़ों, लगभग 80 प्रतिशत लोगों से जुड़ा हुआ ढुद्दा है।...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति : लेकिन...*(व्यवधान)*... How can I allow? ...*(Interruptions)*..

शुश्री ढायावती : यहां पर अच्छी बात यह है कि...*(व्यवधान)*...अगर आप ऐसा करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि आज ढाननीय सदन ढें लॉ ढिनिस्टर भी ढौजूद हैं, ढाननीय प्रधान ढंत्री जी भी ढौजूद हैं और जो ढुद्दा ढें उढाने जा रही हूँ, वह लॉ ढिनिस्टर के ढंत्रालय से संबंढित है।

श्री उपसभापति : लेकिन, ऐसा कैसे कर सकते हैं?

शुश्री ढायावती : ढाननीय उपसभापति जी, यह बहुत ढहतत्वपूर्ण ढुद्दा है।...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति : वह ठीक है। लेकिन, आप इसके लिए नोटिस दीजिए।...*(व्यवधान)*...

शुश्री ढायावती : बहुत नुकसान होने जा रहा है।...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति : आप नोटिस दीजिए।...*(व्यवधान)*...

शुश्री ढायावती : आप ढेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*...आप ढेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*...ढें दो-तीन ढिनट का ही समय लूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी।

12.00 NOON

श्री उपसभापति : आप नोटिस दीजिए।

सुश्री मायावती : देश में एस. सी., एस. टी. और ओ. बी. सी. वर्गों के जो लोग हैं, ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : ऐसा कैसे होगा? ... (व्यवधान)...

सुश्री मायावती : तो उनका अभी कुछ दिन पहले... (व्यवधान)... अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो महत्वपूर्ण... (व्यवधान)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, if you are going to allow one person without a proper notice, then, you have to allow all of us.

सुश्री मायावती : माननीय उपसभापति जी, आप मेरी बात सुन लीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mayawatiji, please listen to me. You give a notice. How can I allow one Member and not allow others. ... (Interruptions)...

सुश्री मायावती : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री उपसभापति : ठीक है। आप नोटिस दीजिए।

सुश्री मायावती : देश में एस. सी., एस. टी. और ओ. बी. सी. वर्गों के जो लोग हैं, जिनकी तादाद कुल मिलाकर 80 प्रतिशत के करीब है।

श्री उपसभापति : आप मेरी बात सुन लीजिए। ... (व्यवधान) ... With all respects, I would request you.

कृपया आप मुझे सुनिए। ... (व्यवधान) ... आप जो मुद्दे उठा रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। It is very important. I accept that. But the point is, we have to go through some procedure and rule. My humble request is, you give a notice. If it is important,...

श्री ब्रजेश पाठक : सर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ... (व्यवधान)...

सुश्री मायावती : क्या जितने महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, सबके लिए नोटिस दिए जाते हैं? ... (व्यवधान)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) : सर, इस मुद्दे पर लोक सभा में बोला गया है। ... (व्यवधान)...

सुश्री मायावती : जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनके लिए नोटिस दिया जाए। ... (व्यवधान) ... इस मुद्दे को लेकर आज लोक सभा नहीं चली है। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपका क्या मुद्दा है, यह अभी भी मेरी समझ में नहीं आया है।

सुश्री मायावती : सर, आप मेरी बात सुन लीजिए। ... (व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Actually I don't know what is the subject.

सुश्री मायावती : सर, आप मेरी बात सुन लीजिए कि देश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के जो लोग हैं, जिनकी जनसंख्या कुल मिलाकर देश की जनसंख्या का 80 प्रतिशत के करीब बन जाती है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : ठीक है, ठीक है।

Review of Supreme Court order on reservation policy in promotions

सुश्री मायावती (उत्तर प्रदेश) : सर, अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इन वर्गों के लोगों को सरकारी संस्थानों में महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर अभी तक जो आरक्षण मिल रहा था, उसको खत्म कर दिया गया है। जब यह आरक्षण खत्म कर दिया गया, तो यह मामला पार्लियामेंट में उठा, लोक सभा में भी उठा, राज्य सभा में भी उठा और पार्लियामेंट के बाहर भी उठा। लोक सभा में माननीय कानून मंत्री जी ने यह कहा था, चूंकि वे यहां बैठे हुए हैं, इसलिए मैं यह बात कह रही हूं, उन्होंने यह कहा था कि हम इस मामले को लेकर जल्दी ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में जाएंगे, लेकिन अभी तक तो ये लोग रिव्यू में नहीं गए हैं।...**(व्यवधान)**...

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : हम रिव्यू में गए हैं।

सुश्री मायावती : बलिए, अच्छी बात है कि आप रिव्यू में गए हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, वह कई राज्यों में लागू हो गया है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बोल चुकी हैं। आपकी बात पूरी हो गई है।...**(व्यवधान)**...

सुश्री मायावती : सर, इसकी वजह से राज्यों में जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोग हैं, उनको इस मामले में बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से यह चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें दखल दें, दिलचस्पी लें, कानून मंत्री जी से मैं यह चाहूंगी, अब यह मामला बहुत गंभीर हो गया है, क्योंकि यह फैसला कई राज्यों में लागू हो गया है।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

सुश्री मायावती : सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस मामले में रिव्यू के चक्कर में न पड़ कर इस पर संवैधानिक संशोधन लाना चाहिए।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You made your point. Please conclude. That is all.

सुश्री मायावती : सर, यदि इस पर संवैधानिक संशोधन नहीं लाया गया, तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। हम चाहेंगे कि कानून मंत्री जी इस पर जवाब दें।...**(व्यवधान)**...